गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : • Email : garvigujarat2007@gmail.comgarvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 338 | दि. 09-04-2019 मंगलवार | वि.सं. 2075 | चैत्र सुद-०४ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

घोषणापत्र में राम मंदिर निर्माण का वादा किया गया

भाजपा का घोषणापत्र जारी : किसानों और छोटे दुकानदारों को पेंशन का वादा

आतंकवाद से कड़ाई से निपटना, तीन साल में किसानों की आय दोगुनी करना, संविधान के अनुच्छेद ३७० को समाप्त करने संबंधी वादे शामिल

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, दोबारा सत्ता में वापसी के लिए मेहनत कर रही भाजपा ने सोमवार को लोकसभा चुनाव २०१९ के लिए जारी अपने घोषणा पत्र में कई वादे किये हैं जिनमें राम मंदिर का तेजी से निर्माण, आतंकवाद से कड़ाई से निपटना, अगले तीन साल में किसानों की आय दोगुनी करना, २०३० तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनान और संविधान के अनुच्छेद ३७० को समाप्त करने संबंधी वादे शामिल हैं। भाजपा मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के लिये पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हम देश को समृद्ध बनाने, सामान्य लोगों के सशक्तीकरण को लेकर जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देते हुए 'एक मिशन, एक दिशा' को लेकर आगे बढ़ेंगे। मोदी ने कहा, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी यह नहीं है कि क्या दिया, बल्कि कसौटी यह होती है कि जो दिया वह अंतिम व्यक्तितक पहुंचा या नहीं ? हम आजादी के ७५ साल में ७५ लक्ष्य लेकर चले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे लोग गरीबी को नहीं हरा सकते। गरीब ही गरीबी को हरा सकती है। यह हमारा मंत्र है और इसलिए गरीबों के सशक्तीकरण को हमने बल दिया है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और किसान उनकी सरकार के कार्यों के केंद्र में हैं और विकास को जनांदोलन बनाना लक्ष्य है। भाजपा ने इस दौरान पांच साल के कामकाज का लेखा जोखा भी रखा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने दावा किया कि जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, २०१४ से २०१९ के पांच साल स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। उन्होंने जोर दिया, हमारी सरकार को बुनियादी जरूरतों को जनता तक पहुंचाने में सफलता मिली है। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम मोदी सरकार ने किया है। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम मोदी सरकार ने किया है। २००४ से २०१४ तक भारत का गौरव हमेशा नीचे गया और नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने देश को एक निर्णायक सरकार दी है। उन्होंने कहा, भारत एक महाशक्ति के तौर पर उभरकर सामने आया है। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में राजग के सभी दल फिर से आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री और पार्टी की संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के मन की बात इस संकल्प पत्र में समाहित की गयी है और जहां जरूरी हुआ है वहां बदलाव करने में भी हमने कोई संकोच नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जनता की हिस्सेदारी को संकल्प पत्र का अहम हिस्सा माना है, साथ ही जन भागीदारी को भी सुनिश्चित किया है। हमने करीब ६ करोड़ लोगों से इस अपने संकल्प पत्र को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं, राजनीतिक पार्टियां घोषणापत्र जारी करती हैं। पहले जो भी वादे अन्य पार्टियों ने किए, वे थोड़े भी पूरे हो गए होते तो भारत आज बहुत आगे होता। इस अवसर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, हमने २०१४ के संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया है। अभी जो हमारा संकल्प पत्र है, वह 'टुकड़े-टुकडे गैंग' की सोच वाला नहीं है बल्कि मजबूत राष्ट्रवादी सोच से तैयार किया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि २०१४ में अनिर्णायक माहौल था और मजबूर सरकार थी। तब भाजपा और हमारे उम्मीदवार नरेंद्र मोदी उम्मीद की तरह आए। आज माहौल बदल चुका है। हम डिलीवर करने वाली सरकार बने हैं। सायबर स्पेस से आउटर स्पेस तक हमने बढ़त बनाई है। उन्होंने कहा कि ये पहले ५ साल हैं जब देश दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना। इतिहास में पहली सरकार है, जिसने गरीबी को सबसे तेजी से खत्म करने का काम किया है। जेटली ने जोर दिया कि पुरानी सरकारों ने सिर्फ नारे दिए। हमारी सरकार ने नतीजे दिए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, हमारे शीर्षक और दूसरों के शीर्षक का अंतर समझें। आज हम घोषणा करने नहीं आए हैं, बल्कि संकल्प का भरोसा देने आए हैं। उन्होंने कहा कि जब वह कहती हैं कि हमने ३४ करोड़ बैंक खाते खोले हैं तो लोग चौंक जाते हैं। पुरानी सरकार में रोज १२ किलोमीटर हाइवे बनते थे इस सरकार में २९ किमी रोज बनते हैं। भारत की उपलब्धि के बारे में जानकर विदेश में लोग चौंक जाते हैं। विदेश के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकर चौंक जाते हैं। सुषमा ने इस दौरान पांच देशों से प्रधानमंत्री को सम्मानित किये जाने और पाकिस्तान की अपत्ति के बावजूद ओआईसी देशों के सम्मेलन में आमंत्रित किये जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे कहना चाहती हूं कि हमारे संकल्प पत्र की तुलना बाकी पार्टियों के घोषणा पत्र से भी करें। हम मजबूत सरकार की वकालत कर रहे हैं, वे गठबंधन के नाम पर मजबूर सरकार की वकालत कर रहे हैं।

बीजेपी के घोषणापत्र पर कांग्रेस का वार

कांग्रेस ने इसे 'झांसापत्र' और झूठ का गुब्बारा करार दिया

बीजेपी जो वादे करती है निभाती नहीं है : जिस तरह के वादे किए गए हैं, चलने वाला नहीं है : अहमद पटेल

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा २०१९ लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणापत्र पर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला है। कांग्रेस ने इसे 'झांसापत्र' और झूठ का गुब्बारा करार दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे अच्छा होता कि बीजेपी माफीनामा जारी कर लेती। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले ५ साल में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस के घोषणापत्र में साफ अंतर देख सकते हैं। कवर पेज पर हमारे घोषणापत्र में लोगों की भीड़ है लेकिन बीजेपी के घोषणापत्र में केवल एक आदमी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणापत्र झूठ का गुब्बारा है। उन्होंने कहा, बीजेपी का घोषणापत्र साइट पर ही रह जाता है। कभी चायवाला, कभी चौकीदार, कभी कामदार और कभी फक्कीर और कभी कुछ और कहकर देश के लोगों को गुमरा किया जा रहा है। पटेल ने कहा, बीजेपी जो वादे करती है वह कभी निभाती नहीं है। जिस तरह के वादे किए गए हैं, यह चलने वाला नहीं है। ५ साल में बीजेपी को हिसाब देना चाहिए कि बेरोजगारी, किसानों और व्यापारियों के लिए जो वादे किए गए हैं उनका क्या हुआ। रोजगार के लिए कोई ठोस कदम इसमें नहीं है। बीजेपी के इस घोषणापत्र का देश से वास्ता नहीं है। बहुत हो गया है, देश की जनता अच्छी तरह से आपको जान चुकी है। कवर पेज पर हमारे घोषणापत्र में लोगों की भीड़ है लेकिन बीजेपी के घोषणापत्र में केवल एक आदमी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणापत्र झूठ का गुब्बारा है। उन्होंने कहा, बीजेपी का घोषणापत्र साइट पर ही रह जाता है। कभी चायवाला, कभी चौकीदार, कभी कामदार और कभी फकीर और कभी कुछ और कहकर देश के लोगों को गुमरा किया जा रहा है। पटेल ने कहा, बीजेपी जो वादे करती है वह कभी निभाती नहीं है। जिस तरह के वादे किए गए हैं, यह चलने वाला नहीं है। अहमद पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि अब न्याय होगा और अब न्याय होकर रहेगा। उन्होंने कहा, झूठ का गुब्बारा ज्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। सब लोगों को हमेशा के लिए गमुराह नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस एक अन्य वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के घोषणापत्र को जुमला और झांसों का पत्र कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर झांसा पत्र तैयार किया है और देश की जनता उनको खारिज करेगी। सुरजेवाला ने २०१४ में बीजेपी द्वारा किए गए वादों की जिक्र कर कहा कि इस घोषणापत्र में काले धन पर बीजेपी चुप है। बेरोजगारी पर भी कोई बात नहीं की गई है। सुरजेवाला ने कहा कि झांसे में फांसो मोदी का मूलमंत्र है।

न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की प्रतिक्रिया

इस बार मंदिर निर्माण नहीं हुआ तो बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ेगा

मंदिर निर्माण हो इसके लिए हिंदू समाज लगातार संघर्ष करता रहा है : बीजेपी के लिए आखिरी मौका है : महंत

(संपूर्ण समाचार सेवा) अयोध्या, बीजेपी के संकल्प पत्र में संभावनाएं तलाश कर सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर निर्माण के लिए हरसंभव कोशिश करने की बात कही गई है। उधर, श्रीराम जन्म भूमि और कृष्ण जन्मभूमि न्यास अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने दो टूक कहा है कि यह आखिरी मौका है। इस बार अगर मंदिर निर्माण नहीं हुआ तो बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ेगा। बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को संकल्प पत्र जारी किया। इसमें पार्टी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। साथ ही पार्टी की तरफ से राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर घोषणापत्र में शामिल हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत गोपालदास ने कहा, बीजेपी की पिछली सरकारों ने भी अपने घोषणापत्र में राम मंदिर निर्माण की बात संवैधानिक आधार पर कराने की बात कही थी। इस वादे के कारण ही देश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत में केंद्र से लेकर प्रदेश तक भेजा। पर यह आखिरी मौका है। महंत ने कहा, राम मंदिर निर्माण हर हिंदू की अपेक्षा है। मंदिर का निर्माण हो इसके लिए हिंदू समाज लगातार संघर्ष करता रहा है। पर, बीजेपी के शासनकाल में संघर्ष की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस बार बीजेपी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किया, लेकिन कार्यकाल पूरा होने के अंतिम दौर में है। हिंदू समाज को विश्वास है कि मोदी सरकार ही मंदिर का निर्माण कराएगी। गोपालदास ने कहा कि इसके लिए मोदी सरकार को प्रारंभ से ही जुटना पड़ेगा। हिंदू समाज को राम मंदिर निर्माण के प्रति गति दिखनी भी चाहिए। मोदी सरकार को आखिरी अल्टिमेटम देते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस बार मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो बीजेपी को सत्ता से दूर होना पड़ेगा। उधर, वीएचपी के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने मोदी सरकार के संकल्प पत्र का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ही अपने घोषणापत्र में राम मंदिर की बात कही है जबकि अन्य दलों के लोग तो केवल मंदिरों का दर्शन कर पूरे समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यह तथाकथित हिंदूवादी लोग केवल स्वांग रच रहे हैं।

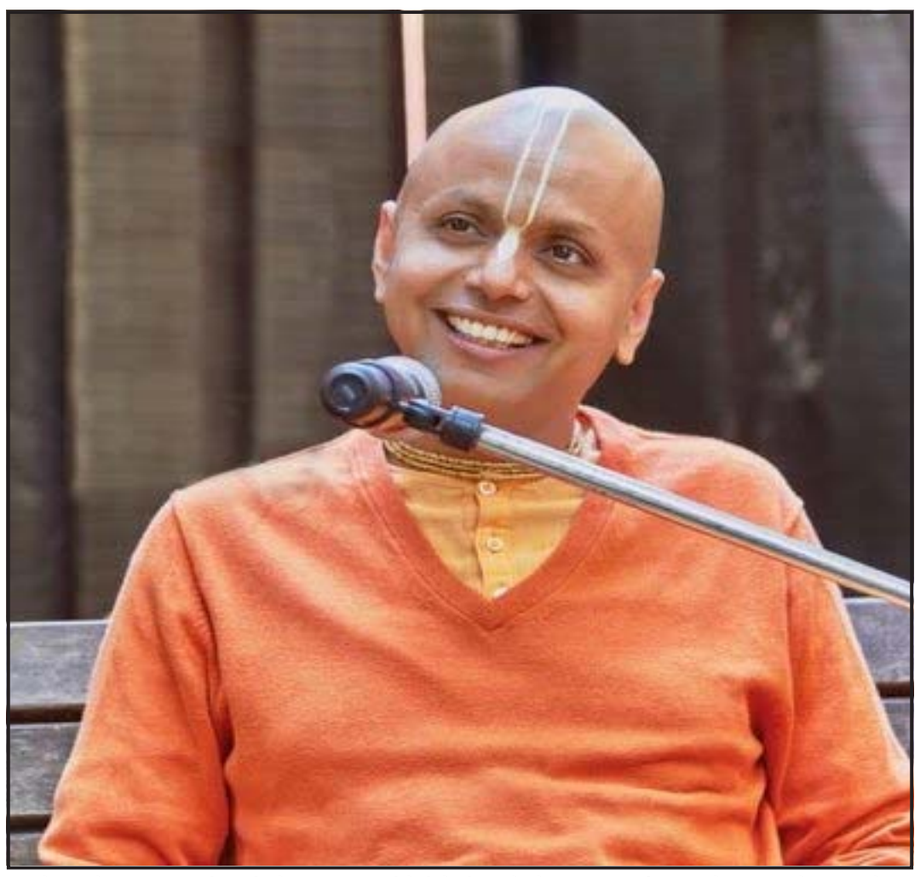

पश्चिम यूपी को साधने वाले थे

खराब मौसम से राहुल और प्रियंका तीनों रैलियां रद्द

(संपूर्ण समाचार सेवा) बिजनौर, लोकसभा चुनाव के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए जोर-शोर से जुटी कांग्रेस का पूरा फोकस यूपी पर है। ८० लोकसभा सीटों पर हर पार्टी कड़ी मेहनत में जुटी है। इसी क्रम में सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को बिजनौर, सहारनपुर और शामली में अलग-अलग चुनावी रैलियों को संबोधित करना था। पर अब खराब मौसम के कारण ये सभी रैलियां रद्द कर दी गई हैं। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने कहा कि मंगलवार को यहां प्रियंका गांधी के रोड शो की तैयारी में पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। दरअसल, बिजनौर इंटर कॉलेज के मैदान में सुबह ११ बजे से राहुल और प्रियंका की रैली होनी थी। इसके बाद राहुल की सहारनपुर के गांधी मैदान में दोपहर साढ़े १२ बजे और शामली के वीवी कॉलेज के मैदान पर दोपहर करीब ढाई बजे सभा होनी थी।

लोकसभा चुनाव : लेह के एक बूथ पर १२ मतदाता

(संपूर्ण समाचार सेवा) लेह, देश में हो रहे आम चुनाव के लिए जम्मू-कश्मीर के लेह में एक ऐसा मतदान केंद्र है जहां सबसे कम मतदाता हैं। इतना ही नहीं सबसे ऊंचाई वाला मतदान केंद्र भी इसी इलाके में है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में ११,३१६ मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लेह जिला निर्वाचन अधिकारी अन्वी लवासा ने बताया कि लद्दाख संसदीय क्षेत्र के लेह विधानसभा में गाइक गांव में एक मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां सबसे कम केवल १२ मतदाता हैं। उन्होंने बताया, गाइक मतदान केंद्र (संख्या ३८) में केवल १२ मतदाता हैं। इनमें पांच पुरुष और सात महिला हैं। अधिकारी ने कहा, इसी तरह इस जिले में सबसे ऊंचाई पर बना मतदान केंद्र भी है। यह समुद्र स्तर से १४,८९० फुट ऊंचाई पर स्थित है। यह मतदान केंद्र अनले पो में है। लवासा ने बताया कि यह दोनों मतदान केंद्र लेह विधानसभा क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में कुल मतदान केंद्रों की संख्या २९४ है। जम्मू-कश्मीर में छह संसदीय सीट है। यहां ७८,४२,९७९ मतदाताओं के लिए ११,३१६ पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।

संपादकिय

चयन के सीमित विकल्प-विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव को मोदी–केंद्रित बना दिया

लोकसभा चुनाव नतीजों को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। वास्तविक स्थिति 23 मई को मतगणना के बाद स्पष्ट होगी। इस दौरान उन प्रवृत्तियों को पक ?ने की कोशिश हो रही है जो परिणामों को प्रभावित कर सकती हैं। विपक्षी दलों ने चुनाव मोदी–केंद्रित बना दिया है या तो आप प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं या उनके खिलाफ। ऐसा बंटवारा कभी साम्यवादी विचारक मार्क्स के बारे में हुआ करता था। ऐसी मान्यता थी कि या तो आप मार्क्सवादी हैं या उसके विरोधी। मार्क्स दार्शनिक विचारक थे, मोदी व्यावहारिक राजनीतिज्ञ हैं। मार्क्स वामपंथी थे। मोदी दक्षिणपंथी हैं पर दोनों उपेक्षितों और वंचितों के लिए चिंतित हैं। राहुल गांधी ने मोदी पर 'सूट–बूट' यानी अमीरों की सरकार होने का आरोप लगाया था और अभी भी यह आक्षेप लगाते हैं कि वह चंद उद्यमियों की चिंता करते हैं। क्या वह सच है ? मोदी सरकार द्वारा 2014 में शुरू जनधन योजना के तहत 30 करो ? से अधिक बैंक खाते खुलवाने से गरीबों के वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया तेज हुई है। गरीबों की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हुई है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ उनके खाते में सीधे आने लगा है। आम चुनावों का तात्कालिक संदर्भ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसग ? में भाजपा की हार और कांग्रेस की जीत है। इससे उत्साहित कांग्रेस ने उप्र में प्रियंका और ज्योदिरादित्य सिंधिया को उतारा। कांग्रेस प्रियंका को 'प्रमोट' कर रही है और उन्हें 'पार्टी–आइकॉन' बनाना चाहती है, लेकिन राजनीति नए दौर में है और 'कॉस्मेटिक–पॉलिटिक्स' का प्रभाव संदिग्ध है। अमेठी और रायबरेली तक में कांग्रेस का जनाधार कमजोर हो चुका है और शायद इसीलिए राहुल को दक्षिण का रुख करना पडा। जिनको मोदी नापसंद हैं उनके लिए इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका आकर्षण का केंद्र हो सकती हैं, पर इंदिरा के विपरीत प्रियंका का राजनीति में न तो कोई दखल रहा है, न दिलचस्पी। जनता उनसे क्यों प्रभावित हो ? उप्र में सपा–बसपा गठजो ? से भाजपा विरोधी माहौल बना जरूर, पर सपा–बसपा अंतर्विरोध और लगभग 40–40 दलीय प्रत्याशियों को टिकट से वंचित करने से साझा उम्मीदवारों के विरुद्ध दोनों दलों में विस्फोटक स्थिति है। मतों के हस्तांतरण की जिस बुनियाद पर गठबंधन बना, वह संकट में है। जहां–जहां सपा प्रत्याशी है वहां दलित मतदाता मोदी को वोट देना चाहता है। जहां बसपा प्रत्याशी है वहां सपा का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और यादव/ओबीसी मतदाता भाजपा की ओर आकर्षित है। जबसे सपा का विघटन हुआ और अखिलेश–शिवपाल का बंटवारा हुआ तबसे सपा का मतदाता पार्टी की धूमिल संभावना देख किसी मजबूत ठौर–ठिकाने की तलाश में है। ऐसी मान्यता है कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते। 1990 के दशक में मुट्ठी भर मुस्लिम भाजपा को वोट देते थे, लेकिन अब भाजपा का मुस्लिम जनाधार बडा है। मोदी सरकार द्वारा तीन–तलाक और हज–सब्सिडी आदि पर जो पहल की गई .उससे मुस्लिम महिलाओं और हाजियों में वह लोकप्रिय हुए हैं।

वायुसेना की जरूरतों की अनदेखी कर कुंडली

(जी.एन.एस.) जब यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात को देखते हुए राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अपने राफेल राग पर लगाम लगाएंगे तब उन्होंने एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर 'चौकीदार चोर' का अपना नारा उछाला। इतना ही नहीं उन्होंने तथ्यों से मुंह चुराते हुए इस सौदे में देरी का आरोप भी मोदी सरकार पर म ? दिया, जबकि हर कोई जानता है कि मनमोहन सरकार कैसे वायुसेना की जरूरतों की अनदेखी कर कुंडली मारे बैठी रही। आखिर राहुल का रवैया खुद को जबरन सही साबित करने वाला नहीं तो और क्या है ? यह तो कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता है। राफेल पर पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राय को हिकारत भरी नजरों से देखना भला और क्या है ? इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने यही सब तो किया था! 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इंदिरा गांधी में यह प्रवृत्ति बलवती होने लगी थी। तब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इंदिरा गांधी एकाधिकारवाद की ओर बड रही हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का नारा तो आपातकाल से पहले ही दे दिया गया था। इस नारे को कांग्रेसी सांसद शशि भूषण ने उछाला था। कांग्रेस नेतृत्व ने उसका कभी विरोध नहीं किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब ?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती

थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल ख ?ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। यानी एक ही तरह के आरोप से घिरे व्यक्ति को कांग्रेस कैग बनाए तो ठीक, पर यदि दूसरे दल की सरकार बना दे तो गलत। यही है कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता! यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि शर्मा या महर्षि के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे या सही। यहां तो सिर्फ दोहरे मापदंड की बात हो रही है। इस पृष्ठभूमि में यह बताना प्रासंगिक है कि कैग जैसी संस्था को हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी अधिक गरिमा प्रदान की और साथ ही प्रथम प्रधानमंत्री ने किस तरह उसका पालन किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब ?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल खडा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। सरकार के अफसर तो प्रधानमंत्री के मातहत होते हैं, पर कांग्रेस की मौजूदा पीडी ने राजनीतिक कारणों से संस्था के प्रति जवाहरलाल नेहरू की भावना की भी परवाह नहीं की। उसे तो बस यही चाहिए कि कोई संस्था उस व्यक्ति को राफेल मामले में दोषी ठहरा दे जिसको कांग्रेस दोषी देखना चाहती है। तभी उसे कांग्रेस के उस प्रथम परिवार के समकक्ष में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने मौजूदा प्रधानमंत्री को ला देने में सुविधा होगी। याद रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के प्रथम परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदार के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कैग की रिपोर्ट के बाद अच्छा होता कि राहुल राफेल पर दोबारा चर्चा करने से बचते। बहरहाल आपातकाल तथा अन्य अनेक कारणों से इंदिरा गांधी की 1977 के चुनाव में पराजय हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। तब लगा था कि कांग्रेस की इमरजेंसी की मानसिकता का खात्मा हो गया, पर कांग्रेस की नई पीडी तो उसे बनाए रखने के पक्ष में लगती है!

ग्रीन हाउस गैसें भीषण गर्मी या टंडी का कारण बन सकती हैं।

(जी.एन.एस.) आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सियोल यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी जीवनशैली जलवायु परिवर्तन के बडे कारणों में से एक है। यह बात शत–प्रतिशत सही है कि हमने जिस तरह की जीवनशैली अपना रखी है वह एक दिन हम सबको डुबो देगी या फिर हमारा दम घोंट देगी। अगर हम मात्र जीवन की कुछ बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित होते तो भी चलता, पर अत्यधिक पाने की लालसा हमारे लिए एक बडे संकट को जन्म दे रही है। दुर्भाग्य यह है कि हम इस बदलते हालात की चर्चा तो कर रहे हैं, पर इन सुविधाओं को त्यागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हर मौसम के बदले से तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं मिली थी ? जॉन टेंडल ने वर्ष 1850 में यह बता दिया था कि ग्रीन हाउस गैसें भीषण गर्मी या ठंडी का कारण बन सकती हैं। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक

परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमश- 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं जो कार्बन उत्सर्जन के खतरे को कम कर सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमने अपने उपयोगों के लिए भयानक रूप से जंगलों का हनन किया है। वर्ष 2017 में अकेले 390 लाख एकड वनों की कटाई हुई। मतलब एक मिनट में एक पेड काटा गया। यह कटाई हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रही है जिसके विकल्प खोजे जा सकते हैं। मसलन टिंबर के लिए 37 फीसद वनों का हनन होता है, वहीं खेती के लिए 28 फीसद, सडक निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में करीब 140 फीसद। इसके अतिरिक्त 21 फीसद वन दावानल की भेंट चड जाते हैं। यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि मीट और मीट उत्पाद से जुडी हमारी खाद्य आदतें भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बडा कारण हैं। दुर्भाग्य यह भी है कि इनके लिए वर्ष 2030 में आज के मुकाबले 67 फीसद ज्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग होगा। मतलब साफ है आने वाले दिनों में ये इंसानों में संक्रमण का एक बडा कारण बनेंगे। एक आकलन है कि वर्ष 2050 तक सालाना 9.5 मिलियन लोग इसका शिकार बनेंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन, निर्माण कार्य एवं कंप्यूटर डाटा जो आज मात्र एक फीसद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण हैं, वर्ष 2040 तक ये 14 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने लगेंगे। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमश- 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं यह इसलिए है, क्योंकि हम एक भोगवादी सभ्यता का बडा हिस्सा बन गए हैं। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो ? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है।जाहिर है हमें यहां प्रकृति और विज्ञान के नियमों को समझने का समय है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। अब जो चर्चा का सबसे बडा विषय होना चाहिए वह यह कि हम अपनी जीवनशैली को ढेर सारी सुविधाओं के दृष्टिकोण से न देखें। संसाधनों का आवश्यकता एवं सुविधा भर उपयोग एक तरफ जहां हमें लंबा जीवन दे सकता है वहीं प्रकृति और पृथ्वी को भी विचलित नहीं करेगा। यह पूरी तरह सच है कि हमारी तेजी से बदलती हुई जीवनशैली ने हमें ऐसे मो ? पर पहुंचा दिया है जहां से आगे जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीने के तौर–तरीकों में सुविधाओं से ज्यादा साधनों के उन तरीकों को अपनाएं जो सततता प्रदान कर सकते हैं।

राधिका मदान का भी फिल्म में महत्वपूर्ण रोल

इरफान खान की 'अंग्रेजी मीडियम' में होंगी करीना

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

पिछले काफी समय से इरफान खान की २०१७ की फिल्म हिंदी मीडियम के सीक्वल की चर्चा है। अब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और इसका नाम अंग्रेजी मीडियम होगा। इस फिल्म में इस बार भी लीड रोल में इरफान खान होंगे और उनके साथ राधिका मदान का भी फिल्म में महत्वपूर्ण रोल होगा। पहले ऐसी चर्चा थी कि इस फिल्म में इरफान के ऑपोजिट करीना कपूर को कास्ट किया जा सकता है। हालांकि करीना और फिल्म की टीम दोनों ने ही इस बात को कन्फर्म नहीं किया था। पिछली फिल्म में इरफान के ऑपोजिट फीमेल लीड रोल पाकिस्तानी ऐक्ट्रेस सबा कमर ने निभाया था। फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया गया था। अब इन अटकलों पर राधिका मदान ने रोक लगा दी है। उन्होंने कन्फर्म किया है कि करीना कपूर को फिल्म में कास्ट किया गया है। राधिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म के शूटिंग के क्लैपबोर्ड को शेयर करते हुए लिखा, इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूं। इस नए सफर के लिए बहुत बहुत आभार इरफान खान, करीना कपूर खान और दिनेश विजान। इस फिल्म में इस बार भी लीड रोल में इरफान खान होंगे और उनके साथ राधिका मदान का भी फिल्म में महत्वपूर्ण रोल होगा। पहले ऐसी चर्चा थी कि इस फिल्म में इरफान के ऑपोजिट करीना कपूर को कास्ट किया जा सकता है। हालांकि करीना और फिल्म की टीम दोनों ने ही इस बात को कन्फर्म नहीं किया था। पिछली फिल्म में इरफान के ऑपोजिट फीमेल लीड रोल पाकिस्तानी ऐक्ट्रेस सबा कमर ने निभाया था। फिल्म में उनके काम को काफी पसंद किया गया था। अब इन अटकलों पर राधिका मदान ने रोक लगा दी है।अब फिल्म की इस कास्ट को देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि इरफान खान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर करीना कपूर पहली बार दिखाई देंगी। अभी इस फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग राजस्थान में चल रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म में राधिका मदान इरफान खान की बेटी के रूप में दिखाई देंगी। इसके बाद फिल्म की टीम शूटिंग के लिए लंदन जाएगी। पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी दीपक डोबरियाल का महत्वपूर्ण रोल होगा।

इरफान के साथ करीना कपूर पहली बार दिखाई देंगी

मोदी कांग्रेस के पंजे से सरकारी संपत्ति की रक्षा कर रहे है : रुपाणी

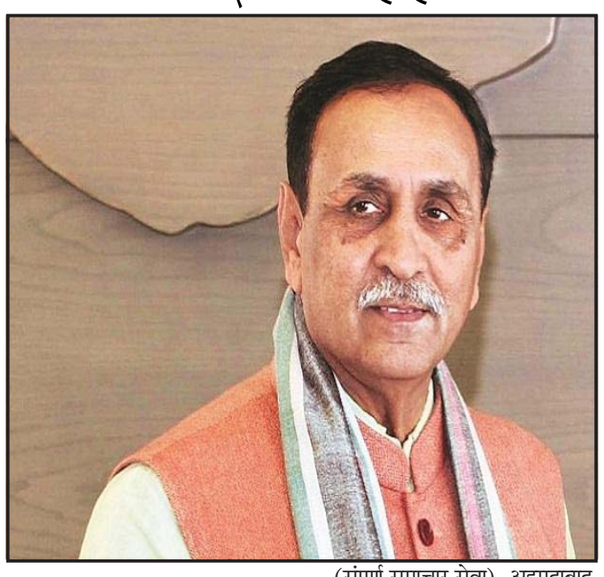

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

रविवार को पाटण के हारीज में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने राज्य सरकार के मंत्रियों, प्रदेश के सीनियर, जिला पंचायत के प्रमुखों, जिला प्रमुख-महामंत्रियों, विधायकों, विभिन्न समाज के के सीनियरों की उपस्थिति में पाटण लोकसभा के भाजपा के उम्मीदवार भरतसिंह डाभी के समर्थन में आयोजित जनसभा में हजारों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया। रुपाणी ने बताया कि, चुनाव प्रचार की शुरूआत हो रही है तब इस बार के चुनाव में चौकीदारों और चोरों के बीच की है। एक तरफ सीमा पर तैनात सैनिक देश की सुरक्षा कर रहे है, दिल्ली में बिराजमान प्रधान सेवक नरेन्द्र मोदी देश कांग्रेस के पंजे से सरकारी संपत्ति का रक्षा कर रहे है। जबकि दूसरी तरफ चोर लोगों की गैंग खड़ी है, चोर-चोर मौसेरे भाई जैसे महामिलावटवाला गठबंधन मोदी हटाओ के नारे लगा रहे है।

छापेमारी इंदौर, भोपाल, गोवा और दिल्ली में हुई

कमलनाथ के करीबियों के ठिकानों पर आइटी की रेड

करीब ५० जगहों पर छापेमारी : कार्रवाई में आईटी के ३०० अधिकारी जुटे : प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली/भोपाल,

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों से जुड़ी करीब ५० जगहों पर छापेमारी की। आयकर विभाग ने यह छापेमारी इंदौर, भोपाल, गोवा और दिल्ली में की है। इस कार्रवाई में आईटी के करीब ३०० अधिकारी जुटे हैं। जिन लोगों के परिसरों में छापेमारी की गई है, उनमें कमलनाथ के पूर्व ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) प्रवीण कक्कड़, पूर्व सलाहकार राजेंद्र मिगलानी, उनके साले की कंपनी के कुछ अधिकारी और उनके भांजे रतुल पुरी की कंपनी पर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सीएम कमलनाथ ने इन रेड के बारे में कोई भी बयान देने से मना कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के ऑपरेशन करने के पीछे कांग्रेस नेताओं के फाइनैंशल मैनेजमेंट को कमजोर करना है। इन छापेमारियों के बाद प्रदेश भर में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर कहा, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निजी सचिव के घर से आयकर विभाग के छापे में करोड़ों रुपये की काली कमाई बरामद हुई। इससे एक बात तो साफ हो गई कि जो चोर है, उसे ही चौकीदार से शिकायत है। उधर, कांग्रेस ने कमलनाथ के करीबी लोगों से संबंधित आयकर विभाग की मुहिम को लेकर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने यहां जारी बयान में कहा, जिस तरह आयकर विभाग ने आज छापे मारे, उससे स्पष्ट हो गया है कि मोदी सरकार लोकसभा चुनावों की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद इस महकमे के अफसरों को कठपुतली की तरह कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनावों की घोषणा होने से ठीक पहले ही कक्कड़ और मिगलानी ने अपने उक्त पदों से इस्तीफा दे दिया था। कक्कड़ के इंदौर, भोपाल स्थित आवास पर छापेमारी की गई है। कक्कड़ का परिवार हॉस्पिटैलिटी समेत विभिन्न क्षेत्रों के कारोबार से जुड़ा है। वहीं, नई दिल्ली में मिगलानी के आवास पर आईटी की टीम तड़के ३ बजे ही पहुंच गई थी।

बीजेपी के जारी किये गए घोषणापत्र में बड़ी बातें.....

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

कांग्रेस के बाद बीजेपी ने भी सोमवार को अपने घोषणापत्र से पर्दा उठा दिया। संकल्प पत्र नाम से जारी बीजेपी के चुनावी वादों की इस पोटली में जहां किसानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश है, वहीं राम मंदिर, कश्मीर में धारा ३७० व ३५ के संकल्प के जरिए धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ने का इरादा भी है। इसके साथ ही पार्टी की ओर से २०२२ में आजादी की ७५वीं वर्षगांठ के लिए ७५ टारगेट भी तय किए गए हैं। पार्टी की ओर से कहा गया है कि मोदी सरकार के पिछले ५ साल के कार्यकाल के आधार पर इन लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। बीजेपी के घोषणापत्र में सबसे बड़े चुनावी वादे नीचे के अनुसार है।

मंदिर पर संकल्प

बीजेपी के संकल्प पत्र में बीजेपी ने राम मंदिर पर अपने रुख को दोहराया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि मंदिर के जल्द निर्माण के लिए संविधान के दायरे में सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में धारा 35A और ३७० पर वादा

घोषणापत्र में कहा गया है कि पार्टी जम्मू-कश्मीर से धारा 35A हटाने की कोशिश करेगी। घोषणा पत्र में धारा 35 A को जम्मू-कश्मीर के गैर स्थाई निवासियों और महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण बताया गया है। इसके साथ ही धारा ३७० पर भी दृष्टिकोण को दोहराया गया है।

छोटे किसानों के लिए पेंशन

सभी किसानों को ६ हजार रुपये का लाभ मिलेगा। सभी छोटे और सीमांत किसानों को ६० साल के बाद पेंशन की सुविधा देंगे। हम देश में सभी सीमांत और छोटे किसानों के लिए पेंशन की योजना आरंभ करेंगे ताकि ६० वर्ष के बाद भी उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। २०२२ तक किसानों की आय दोगुनी करने का संकल्प। ब्याजमुक्तकिसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा- एक से ५ वर्ष तक के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपये तक के नए अल्पावधि कृषि ऋण मूल राशि के समय पर भुगतान की शर्त भी प्रदान करेंगे।

छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन

देश के छोटे दुकानदारों को ६० साल के बाद पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। पीएम मोदी ने कहा, गांव, गरीब और किसानों पर हमारा फोकस। राष्ट्रवाद के प्रति हमारी पूरी प्रतिबद्धता है। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जबतक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा यह जीरो टॉलरेंस रहेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड को लागू करेंगे। भारत में घुसपैठ को रोकने की कोशिश करेंगे।

एक साथ चुनाव का भी संकल्प

बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में देश में एक साथ चुनाव के विचार को फिर दोहराया है। पार्टी ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर पार्टियों के साथ बातचीत कर अपनी कोशिश जारी रखेगी।

प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान

प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान। अधिक से अधिक ग्रामीण परिवारों को एलपीजी गैस सिलिंडर। पीएम ने कहा २०४७ का भारत बनाने के लिए हमें आज से ही काम करना होगा।

आयुष्मान भारत

आयुष्मान भारत के १.५ लाख हेल्थ और वेयरनेस सेंटर खोले जाएंगे। पीएम ने कहा कि आज के युवा ही देश का भविष्य तय करेंगे। आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम आज एक बेहतर देश बनाने के सपने को लेकर चल रहे हैं।

समान नागरिक संहिता

बीजेपी ने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता को शामिल कर इसे लैंगिक समानता से जोड़ा है। पार्टी के मुताबिक, पार्टी सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से प्रेरित समान नागरिक संहिता बनाने के लिए कटिबद्ध है।

२०२२ के लिए ७५ संकल्प

बीजेपी के घोषणापत्र में २०२२ के लिए बीजेपी ने अपने ७५ संकल्पों को भी शामिल किया है। घोषणापत्र में मोदी सरकार की पिछले ५ साल की उपलब्धियों के आधार पर २०२२ के लिए ७५ टारगेट तय किए गए हैं।

ट्रांसजेंडर्स के लिए भी वादा

बीजेपी ने इसके साथ ही अपने संकल्प पत्र में ट्रांसजेंडर्स के लिए भी संकल्प लिया है। ट्रांसजेंडर्स को समाज की मुख्य धारा में लाने और सशक्तीकरण का वादा भी किया गया है।

कांग्रेस दामाद की चिंता करने में व्यस्त : रुपाणी

भाजपा किसी एक परिवार की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है

मुख्यमंत्री रुपाणी ने पाटण लोकसभा सीट के राधनपुर में जनसभा को संबोधित कर प्रचार की शुरूआत की

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने पाटण लोकसभा सीट के राधनपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, चुनाव प्रचार की शुरूआत हो चुकी है। चुनाव का मुख्य एक ही मुद्दा है। देश के किसके हाथ में सुरक्षित? देश की सुरक्षा करने के लिए कौन सक्षम ५६ की छातीवाला प्रधानमंत्री चाहिए या डरपोक, वोट बैंक की राजनीति करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए? यह चुनाव चौकीदार विरूद्ध चोरों का चुनाव है। मैं भी चौकीदार हूं के नारे के साथ देशभर के लोग देश के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़े हैं। नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि, वह प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है, चौकीदार है। रुपाणी ने बताया कि, जिस तरीके से शरीर के स्वास्थ्य के लिए मिलावट हमेशा नुकसानकर्ता होता है इस तरह महागठबंधन के नाम पर बनाई गई महामिलावट गैंग भी देश के खतरे के लिए नुकसानकारक है। वह बताते है कि, मोदी हटाओ और पीएम मोदी कहते है कि, घोटाला हटाओ। वह कहते है कि, मोदी हटाओ, और मोदी कहते है कि, गरीबी हटाओ, देश की जनता को निश्चित करना है कि, किसे हटाना है। यह महामिलावटी नेता जब सत्ता में थे तब काफी घोटाला किया। परिवारों-रिश्तेदारों को मालामाल कर दिया इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचितों की कोई चिंता नहीं की है। ''चोर मचाये शोर'' वाक्य को योग्य साबित करके आज यह चोर चौकीदार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चोर कहने के लिए निकले है। लेकिन देश के चौकीदार चोर नहीं एकदम प्योर है, और यह देश की ईमानदारी से सेवा कर रहे है। उनका एक ही सूत्र है, ''खाते नहीं है या खाने नहीं देते है'' कांग्रेस अपने दामाद की चिंता करने में व्यस्त है। हेलिकॉप्टर घोटाले में आरजी., एपी, जैसे नाम सामने आ रहे है। दलाली और बेइमानी जैसे कांग्रेस का पर्याय बन गया है। रुपाणी ने राहुल गांधी निशाना साधते हुए कहा कि, कांग्रेस को लालकृष्ण आडवाणी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आडवाणी हमारे लिए पितातुल्य है, उनका सम्मान किस तरीके से बनाये रखे यह भाजपा अच्छी तरीके से जानती है। कांग्रेस अपनी चिंता करे। मैं भी चौकीदार हूं के नारे के साथ देशभर के लोग देश के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ खड़े हैं। नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि, वह प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक है, चौकीदार है। रुपाणी ने बताया कि, जिस तरीके से शरीर के स्वास्थ्य के लिए मिलावट हमेशा नुकसानकर्ता होता है इस तरह महागठबंधन के नाम पर बनाई गई महामिलावट गैंग भी देश के खतरे के लिए नुकसानकारक है। वह बताते है कि, मोदी हटाओ और पीएम मोदी कहते है कि, घोटाला हटाओ। वह कहते है कि, मोदी हटाओ, और मोदी कहते है कि, गरीबी हटाओ, देश की जनता को निश्चित करना है कि, किसे हटाना है। यह महामिलावटी नेता जब सत्ता में थे तब काफी घोटाला किया। परिवारों-रिश्तेदारों को मालामाल कर दिया इसके अलावा कुछ भी नहीं किया।भूतकाल में सरदार वल्लभभाई पटेल, आंबेडकरजी, राममनोहर लोहियाजी, जयप्रकाश नारायणजी जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने का काम कांग्रेस ने किया है। भाजपा किसी एक परिवार या नेताओं की नहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है भाजपा सबका साथ, सबका विकास के मंत्र साथ चलने वाली पार्टी है। इसी वजह से आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

डे. मामलतदार की भर्ती प्रक्रिया का मामला

उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने देने के लिए आदेश

प्रीलिम में सही जवाब दिए गए फिर भी वंचित रखे गए उम्मीदवारों की रिट में हाईकोर्ट का महत्व का आदेश

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

राज्य में डेप्युटी सेक्शन ऑफिसर और डेप्युटी मामलतदार सहित की विभिन्न जगहों के लिए जीपीएससी द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में कई उम्मीदवार जीपीएससी शासकों की गलती की वजह से अलग रहे होने से उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी दी और मुख्य परीक्षा के लिए उनके ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करने और उनको मुख्य परीक्षा में बैठने देने की मांग करती अलग-अलग अर्जी की गई थी। जिसकी सुनवाई में जस्टिस निलय वी. अंजारीया ने महत्वपूर्ण आदेश में, अर्जीकर्ता उम्मीदवारों के मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन फॉर्म पेश करने की मंजूरी दी। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने जीपीएससी शासकों को यह अर्जीकर्ता उम्मीदवारों के यह फॉर्म स्वीकार करने के बाद उनको मुख्य परीक्षा में बैठने देने का आदेश दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने यह अर्जीकर्ता उम्मीदवारों के परिणाम करके रखने के लिए और हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए जीपीएससी शासकों को आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने केस की आगे की सुनवाई १ मई को रखी गई थी। अर्जीकर्ता उम्मीदवारों में नीलेश एच. पटेल तथा अन्य द्वारा की गई अलग-अलग अर्जी में वकील शार्विल पी. मजमुदार ने पेशकश करते हुए बताया कि, जीपीएससी शासकों द्वारा राज्य में डेप्युटी सेक्शन ऑफिसर और डेप्युटी मामलतदार सहित की संबंधित जगहों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें ली जाने वाली प्रीलिमनरी परीक्षा में अर्जीकर्ता उम्मीदवार भी बैठे थे लेकिन बाद में जीपीएससी शासकों ने अर्जीकर्ता के प्रीलिम में मार्क्स कम होने का कारण बताकर उनको मुख्य परीक्षा में बैठने देने के मामले में ऑनलाइन फॉर्म स्वीकार करने का इनकार किया था। जीपीएससी शासकों के यह अन्यायी रवैये की वजह से अर्रजीकर्ता मुख्य परीक्षा में बैठने की योग्यता होने के बावजूद भी वह नौकरी मौके से वंचित रह जाए ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। जिसकी सुनवाई में जस्टिस निलय वी. अंजारीया ने महत्वपूर्ण आदेश में, अर्जीकर्ता उम्मीदवारों के मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए ऑनलाइन फॉर्म पेश करने की मंजूरी दी। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने जीपीएससी शासकों को यह अर्जीकर्ता उम्मीदवारों के यह फॉर्म स्वीकार करने के बाद उनको मुख्य परीक्षा में बैठने देने का आदेश दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने यह अर्जीकर्ता उम्मीदवारों के परिणाम करके रखने के लिए और हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए जीपीएससी शासकों को आदेश दिया गया था। हाईकोर्ट ने केस की आगे की सुनवाई १ मई को रखी गई थी।अर्जीकर्ता उम्मीदवारों की तरफ से वकील शार्विल पी. मजमुदार ने हाईकोर्ट को बताया था कि, अर्जीकर्ताओं के मार्क्स प्रीलिम में कम नहीं लेकिन जीपीएससी शासकों ने मार्कस का सही मूल्यांकन करने में गंभीर लापरवाही बरती है।

मुख्यमंत्री की जनसभा ८ तारीख को आयोजित होगी

विद्यानगर में मोदी की १० तारीख की जनसभा स्थगित

प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा अब नये कार्यक्रम के अनुसार, १७ अप्रैल को आयोजित किए जाने की संभावना

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आणंद जिले के वल्लभ विद्यानगर में १० अप्रैल को आयोजित होनेवाली जनसभा का कार्यक्रम स्थगित रहा है। अब नए कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा अब आगामी १७ अप्रैल को आयोजित किए जाने की संभावना है। दूसरी तरफ, कांग्रेस के गढ़ में आणंद में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी खुद आगामी ८ अप्रैल को है। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा १० अप्रैल को थी, लेकिन फिलहाल यह स्थगित रही है। कांग्रेस के गढ़ ऐसे बोरसद तहसील में भाजपा ने प्रचार मुख्यमंत्री रुपाणी को मैदान में उतारा है। पामोल की चारों तरफ दावोल, बोदाल, दहेमी, नापा में कांग्रेस के वर्चस्व वाली होने से सोमवार को मुख्यमंत्री सहित भाजपा के स्थानीय और प्रदेश स्तर के नेता उतरेंगे और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब नए कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा अब आगामी १७ अप्रैल को आयोजित किए जाने की संभावना है। दूसरी तरफ, कांग्रेस के गढ़ में आणंद में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी खुद आगामी ८ अप्रैल को है। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा १० अप्रैल को थी, लेकिन फिलहाल यह स्थगित रही है। कांग्रेस के गढ़ ऐसे बोरसद तहसील में भाजपा ने प्रचार मुख्यमंत्री रुपाणी को मैदान में उतारा है।मुख्यमंत्री विजय रुपाणी जनसभा को संबोधित करेंग। इसके साथ भाजपा के अन्य नेता भी प्रचार के दौरान उपस्थित होंगे।

विवेक ओबेरॉय फिल्म 'पीएम नरेन्द्र मोदी' को लेकर सुर्खियों में

(संपूर्ण समाचार सेवा) वडोदरा,

बॉलिवुड ऐक्टर विवेक ओबेरॉय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'पीएम नरेन्द्र मोदी' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में वह भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का रोल प्ले कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। विवेक अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए पारुल यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक डायलॉग सेशन में कहा कि अगर वह पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं तो वह २०२४ के लोकसभा चुनाव में वडोदरा से चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने पीएम नरेन्द्र मोदी को प्यार और समर्थन दिया था, जब वह यहां से चुनाव लड़े थे। इस दौरान ऐक्टर ने बताया कि उनकी फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी है, जो देश के प्रधानमंत्री बने और बिना किसी समर्थन या जातिगत राजनीति के दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। गौरतलब है कि डायरेक्टर उमंग कुमार की फिल्म की रिलीज टाइमिंग को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं। इस बीच उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। विवेक अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के लिए पारुल यूनिवर्सिटी पहुंचे थे। यहां उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक डायलॉग सेशन में कहा कि अगर वह पॉलिटिक्स में शामिल होते हैं तो वह २०२४ के लोकसभा चुनाव में वडोदरा से चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों ने पीएम नरेन्द्र मोदी को प्यार और समर्थन दिया था, जब वह यहां से चुनाव लड़े थे। उनका कहना है कि फिल्म लोकसभा चुनाव के बीच रिलीज हो रही है, जिससे इलेक्शन प्रभावित होगा। बता दें, फिल्म की टीम 'पीएम नरेन्द्र मोदी' को ३८ देशों में रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है। इसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएई जैसे देश शामिल हैं।

वीरेन्द्र माथुर को एटीएस-क्राइम ने गिरफ्तार किया

पेपर लीक घोटाले का मास्टर माइन्ड दिल्ली से गिरफ्तार हुआ

नेशनल-इन्टरनेशनल खिलाड़ियों को तैयार करने वाले वेट लिफ्टिंग कोच ने कई पेपर लीक किए जाने का खुलासा

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

गुजरात में खलबली मचाने वाले लोक रक्षक दल की परीक्षा पेपर लीक घोटाले में मुख्य आरोपी और मास्टरमाइन्ड ऐसा प्रोफेशनल गैंग का लीडर वीरेन्द्र माथुर आखिर में दिल्ली से गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले कई दिनों से निगरानी में रही गुजरात एटीएस और शहर क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने वीरेन्द्र माथुर को गिरफ्तार करके बहुत बड़ी सफलता हासिल की। वीरेन्द्र ने पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए है अब पुलिस इसका रिमांड लेकर केस संबंधित महत्व की कडियों का सामाधान लाया जाएगा। लोक रक्षक दल की परीक्षा पेपर लीक घोटाले में गुजरात एटीएस ने और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन शुरू करके मास्टरमाइंड और पेपर लीक करने वाली गैंग के लीडर वीरेन्द्र माथुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। वेट लिफ्टिंग का शोखीन माथुर नेशनल स्पर्धा में हिस्सा ले चुका है और इसके नीचे ६५० वेट लिफ्टर तैयार हुए है जिसमें से १२ इन्टरनेशनल और २०० नेशनल मेडल जीते है। टेक्निकल रिसोर्सिस और सर्वेलन्स के आधार पर दिल्ली के रोहिणी से गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। गिरफ्तार किया गया आरोपी वीरेन्द्र की प्राथमिक पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आये है। इसके अनुसार, पेपर लीक में पहले गिरफ्तार किए गए आरोपी विनय अरोरा और इसके साथ विनोद चिक्कारा इसने परीक्षा के दो दिन पहले ही सोल्व किए गए प्रश्नपत्र दिया था। इसके बदले में वीरेन्द्र को एक करोड़ देना था। वीरेन्द्र ने पेपर बेचने के लिए मोनू का संपर्क किया था। जिसने गुजरात सहित अन्य राज्यों में पेपर लेने के लिए मांगते उम्मीदवारों का संपर्क था। २०१८ में २ दिसम्बर पहले मोनू एक दिन पहले गुजरात के उम्मीदवारों को दिल्ली ले गया था। जहां सभी को अलग जगहों पर पेपर पढ़ाकर याद करने के लिए कहता था। चार घंटे पेपर पढ़ाने के बाद विनोद पेपर ले चला गया था। वीरेन्द्र ने विनोद को पेपर के एडवान्स के तहत ९.७० लाख रुपये दिया था। हालांकि पेपर रद्द होने पर विनोद ने फोन करके परीक्षा रद्द होने की जानकारी वीरेन्द्र को जानकारी दी थी।

देखता हूं कौन इनका झंडा उठाता हैं : फारूक

आर्टिकल ३७० खत्म करके दिखाएं : फारूक अब्दुल्ला

वे समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे : हम क्या सोते रहेंगे ? : फारूक अब्दुल्ला

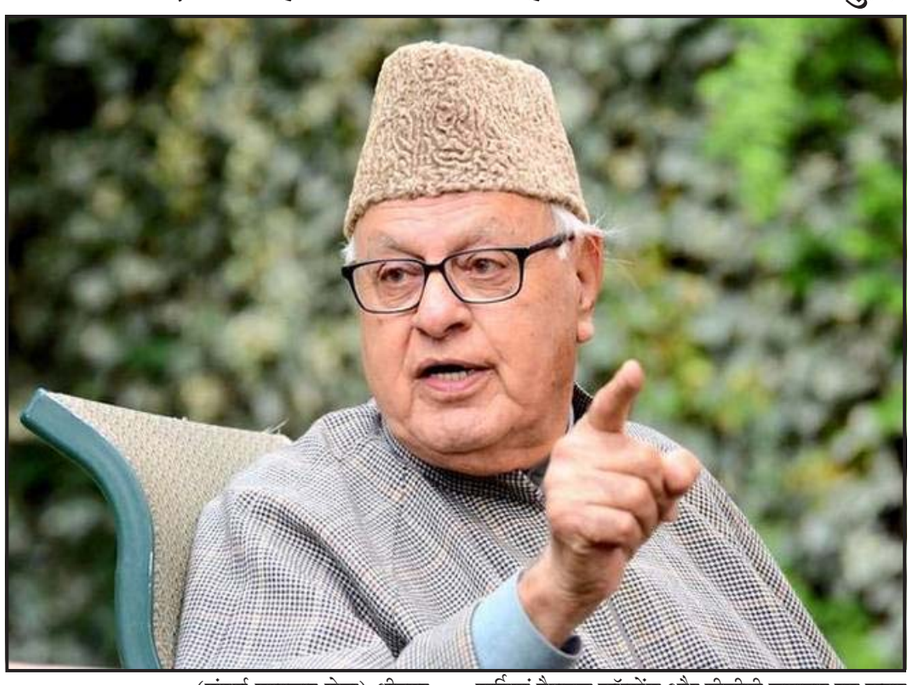

(संपूर्ण समाचार सेवा) श्रीनगर,

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार वादा कर रही है कि वह सत्ता में आई तो संविधान के अनुच्छेद ३७० को समाप्त कर दिया जाएगा। जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी लगातार इस कदम का विरोध कर रही हैं। अब नैशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि ३७० खत्म करके दिखाएं हम भी देखते हैं। फारूक ने यह भी कहा कि अल्लाह को यही मंजूर होगा कि हम इनसे आजाद ही हो जाएंगे। फारूक ने कहा, वे समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे। हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे ? हम इसका मुकाबला करेंगे। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ३७० कैसे खत्म करोगे ? अल्लाह की कसम अल्लाह को यही मंजूर होगा कि हम इनसे आजाद हो जाएंगे। मैं भी देखता हूं फिर कि कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होता है !फारूक ने कहा, वे समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे। हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे ? हम इसका मुकाबला करेंगे। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे।ऐसी चीजें मत करो, जिससे तुम हमारे दिलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। गौरतलब है कि अनुच्छेद ३७० भारतीय संविधान का वह हिस्सा है, जो जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। इसके तहत रक्षा क्षेत्र, विदेश मामलों और फाइनैंस और संचार को छोड़कर बाकी सभी कामों के लिए संसद को राज्य की मंजूरी की जरूरत होती है।

वर्ल्ड कप के लिए १५ अप्रैल को टीम की घोषणा होगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

इंग्लैंड की मेजबानी में होने वाले आगामी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा १५ अप्रैल को होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर सिलेक्शन कमिटी और टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली अगले सोमवार को मुंबई में बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक, विराट के साथ इस कमिटी की बैठक के बाद ही टीम की घोषणा की जाएगी। वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ३० मई को खेला जाएगा और टूर्नमेंट का फाइनल १४ जुलाई को होगा। २ बार के चैंपियन भारत की संभावित टीम हालांकि तय मानी जा रही है लेकिन नंबर-४ के लिए किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, यह बैठक में चर्चा का बड़ा मुद्दा हो सकता है। भारतीय टीम इस वैश्विक टूर्नमेंट में अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ ५ जून को खेलेगी।

२६ सीटों पर ५७३ प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे

४ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए ८३ उम्मीदवार ने पर्चे भरे

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

राज्य में लोकसभा की २६ सीटों पर ५७३ प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे। वहीं राज्य की ४ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए ८३ उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। गुजरात में २३ अप्रैल को मतदान होने हैं। इस बार के चुनाव में सबसे ज्यादा ५७३ प्रत्याशियों ने नामांकन भरे। नामांकन के अंतिम दिन सबसे ज्यादा ३१३ प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। शुक्रवार को नामांकन पत्रो की जांच की गई। इस बार के चुनाव में मुख्य दावेदारों में गांधीनगर सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, दाहोद सीट से जशवंतसिंह भाभोर, अमरेली सीट से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व कांग्रेस प्रत्याशी परेश धानाणी, दाहोद से भाजपा के पूर्व सांसद और अब कांग्रेस से प्रत्याशी बाबू कटारा शामिल है। अब तक के लोकसभा चुनावों पर गौर करे तो यह पता चलेगा कि गत वर्ष २०१४ के चुनाव में ३३४ उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें ३१८ पुरुष व १६ महिलाए थी। इनमें से २८२ उम्मीदवारों की जमानत जप्त हो गई थी। नामांकन के अंतिम दिन सबसे ज्यादा ३१३ प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। शुक्रवार को नामांकन पत्रो की जांच की गई। इस बार के चुनाव में मुख्य दावेदारों में गांधीनगर सीट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, दाहोद सीट से जशवंतसिंह भाभोर, अमरेली सीट से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता व कांग्रेस प्रत्याशी परेश धानाणी, दाहोद से भाजपा के पूर्व सांसद और अब कांग्रेस से प्रत्याशी बाबू कटारा शामिल है। पिछले चुनाव में भाजपा ने सभी २६ सीटें जीती थी वहीं कांग्रेस खाता भी नहीं खोल सकी थी। कांग्रेस ने इस बार किसी भी दल से गठबंधन नहीं किया है। २०१४ में कांग्रेस ने एनसीपी ने सीटों पर समझौता किया था जिसके तहत पोरबंदर सीट एनसीपी को दी गई थी।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तंज

बापू ने १९४७ में कहा था कांग्रेस का काम समाप्त

अब विसर्जन करेंगे राहुल गांधी और प्रियंका : योगी

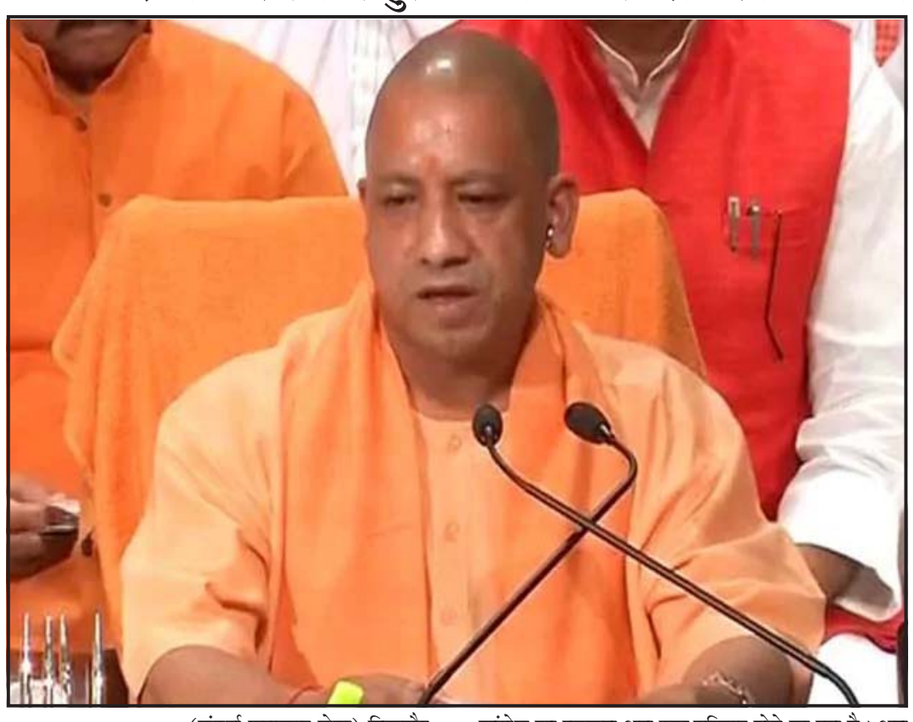

(संपूर्ण समाचार सेवा) बिजनौर,

यूपी की सियासत में आजकल चुभते बोल खूब सुनाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर बरसे। योगी ने कहा कि १९४७ में बापू (महात्मा गांधी) ने कहा था कि कांग्रेस का काम समाप्त हो गया है, अब कांग्रेस का विसर्जन कर दो। वह जानते थे कि कांग्रेस का मतलब अब एक परिवार होने जा रहा है। अब पार्टी का विसर्जन होगा। यूपी सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बापू के सपने को साकार करने के लिए भाई-बहन आ चुके हैं। दोनों पार्टी का विसर्जन करेंगे। योगी ने बिजनौर से कांग्रेस प्रत्याशी (नसीमुद्दीन सिद्दीकी) पर तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है वह तो उनसे भी बड़ा भागी है। भाई-बहन (राहुल और प्रियंका)का जो प्रत्याशी है, उसने पिछली बार बहन जी (मायावती) को जीरो पर पहुंचा दिया था। अब इस बार भाई-बहन को जीरो पर पहुंचा देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यूपी सीएम का कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला यहीं नहीं थमा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता देश में पाकिस्तान का झंडा फहारने की इसीलिए उनके नामांकन के दौरान तिरंगे की जगह पाकिस्तान का चांद-सितारा फहाराया गया। बिजनौर महात्मा विदुर की धरती है। विदुर ने ही द्रौपदी के चीरहण पर उसके खिलाफ बोलने का साहस किया था। कांग्रेस का मतलब अब एक परिवार होने जा रहा है। अब पार्टी का विसर्जन होगा। यूपी सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बापू के सपने को साकार करने के लिए भाई-बहन आ चुके हैं। दोनों पार्टी का विसर्जन करेंगे। योगी ने बिजनौर से कांग्रेस प्रत्याशी (नसीमुद्दीन सिद्दीकी) पर तंज कसते हुए कहा, मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्रत्याशी दिया है वह तो उनसे भी बड़ा भागी है। भाई-बहन (राहुल और प्रियंका)का जो प्रत्याशी है, उसने पिछली बार बहन जी (मायावती) को जीरो पर पहुंचा दिया था। इस चुनावी समर की सबसे बड़ी जंग उत्तर प्रदेश में ही लड़ी जानी है। जहां ७ चरणों मतदान है। २३ मई को काउंटिंग होगी।

विवादित बयानों और टिप्पणी का मामला

राहुल गांधी-सूरजेवाला के विरूद्ध मेट्रो कोर्ट का समन्स

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला के विरूद्ध अहमदाबाद की मेट्रो कोर्ट में अहमदाबाद डिस्ट्रीक्ट कॉर्पोरेटीव बैंक के चेयरमैन अजय पटेल द्वारा मानहानि की दर्ज कराई गई अलग-अलग शिकायत के केस में सोमवार को घीकांटा स्थित मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायाधीश एसके. गढवी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला के विरूद्ध समन्स जारी किया गया है और २७ मई को यह दोनों महानुभाव को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने शिकायतपक्ष के गवाहों की गवाही और सबूतों को जांचने के बाद यह केस में सबसे पहले मानहानि होने का निष्कर्ष दिया था और इसी वजह से प्रतिवादी के विरूद्ध सोमवार को समन्स जारी किया गया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के इस समन्स की वजह से लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी सहित के नेताओं की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी तरफ, यह समन्स को लेकर चुनाव की राजनीति गर्मा गई है। नोटबंदी के दौरान रणदीप सूरजेवाला और राहुल गांधी द्वारा किए गए कई विवादित ट्वीट और टिप्पणी को लेकर एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल द्वारा मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें एडीसी बैंक के चेयरमैन की तरफ से वकील अजीतसिंह जाडेजा ने महत्व की दलीलें देते हुए कहा कि, नोटबंदी के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला द्वारा पत्रकार परिषद करके अमित शाह और एडीसी बैंक के विरूद्ध नोटबंदी के दौरान पांच ही दिन में ७४५ करोड़ रुपये बदले जाने का गंभीर आरोप लगाया था। २७ मई को यह दोनों महानुभाव को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने शिकायतपक्ष के गवाहों की गवाही और सबूतों को जांचने के बाद यह केस में सबसे पहले मानहानि होने का निष्कर्ष दिया था और इसी वजह से प्रतिवादी के विरूद्ध सोमवार को समन्स जारी किया गया। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के इस समन्स की वजह से लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी सहित के नेताओं की परेशानी बढ़ गई है। दूसरी तरफ, यह समन्स को लेकर चुनाव की राजनीति गर्मा गई है। नोटबंदी के दौरान रणदीप सूरजेवाला और राहुल गांधी द्वारा किए गए कई विवादित ट्वीट और टिप्पणी को लेकर एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल द्वारा मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई है, दोनों नेताओं के इस प्रकार के विवादित बयानों को लेकर अहमदाबाद डिस्ट्रीक्ट कॉर्पोरेटीव बैंक की छवि को नुकसान पहुंचा है और वर्षों पुरानी इसकी प्रतिष्ठा को हानि हुई है। विशेष करके जमाकर्ताओं-खाताधारकों के मन में एडीसी बैंक के मजबूत विश्वास को ठेस पहुंचा है।

शिकायतपक्ष की तरफ से महत्व के सबूत पेश

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

एडीसी बैंक के चेयरमैन अजय पटेल की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के केस में वकील अजीतसिंह जाडेजा ने महत्व के सबूत पेश किए। जिसमें कांग्रेस के दोनों राष्ट्रीय नेताओं द्वारा की गई पत्रकार परिषद की सीडी, प्रेस रिलीज की कोपी, राहुल गांधी ने उस समय में ट्वीट करके शाह ज्यादा खा गये कहकर एक तरीके से एडीसी बैंक के पैसे भाजपा में ट्रान्सफर हुए होने का आरोप लगाया था यह ट्वीट के सबूत कोर्ट के रिकॉर्ड पर पेश किया गया था। जिसे ध्यान में लेकर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने यह सबूतों पर से प्रथम दृष्टि में मानहानि होने का निरीक्षण करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सूरजेवाला के विरूद्ध समन्स जारी किया गया।

मायावती ने मेरठ में मोदी सरकार पर निशाना साधा

नमो नमो करनेवालों की जमानत जब्त करा देंगे जय भीम वाले

नोटबंदी, जीएसटी को तैयारी के बगैर लागू किया गया, जिससे देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ी : मायावती

(संपूर्ण समाचार सेवा) मेरठ,

बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को मेरठ में केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर जमकर निशाना साधा। मेरठ लोकसभा सीट से गठबंधन उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी वाले चाहे कितना भी नमो-नमो करें, जय भीम वाले उनकी जमानत जब्त करा देंगे। बीएसपी मुखिया ने कहा, देश में दलित, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ा है। खासकर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां उत्पीड़न ज्यादा है। गरीब सवर्णों का १० फीसदी आरक्षण से उत्थान होने वाला नहीं है। मायावती ने नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, दोनों को तैयारी के बगैर लागू किया गया, जिससे देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ी। छोटे और मध्यमवर्गीय व्यापारी दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए मायावती ने कहा, बीजेपी ने कांग्रेस की तरह ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाकर कमजोर करने की कोशिश की है, जो लगातार जारी है। आजादी के बाद से केंद्र में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों की सरकारें रहीं। इन्हें देश की जनता कई बार आजमा चुकी है, अब ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। मायावती ने कहा, बीजेपी ने २०१४ के चुनावी वादे पूरे नहीं किए। १५ लाख रुपये खाते में नहीं आए, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलीं। बीएसपी मुखिया ने कहा, देश में दलित, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ा है। खासकर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां उत्पीड़न ज्यादा है। गरीब सवर्णों का १० फीसदी आरक्षण से उत्थान होने वाला नहीं है। मायावती ने नोटबंदी और जीएसटी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, दोनों को तैयारी के बगैर लागू किया गया, जिससे देश में गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ी। छोटे और मध्यमवर्गीय व्यापारी दुखी हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए मायावती ने कहा, बीजेपी ने कांग्रेस की तरह ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाकर कमजोर करने की कोशिश की है, जो लगातार जारी है। कांग्रेस ने गरीबों को हर माह छह हजार देने की बात कही लेकिन इससे कोई भला नहीं होगा। गठबंधन की सरकार बनने पर हर गरीब को छह हजार रुपये की जगह, सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में स्थायी रोजगार देने का कार्य करेंगे।

मुलायम सिंह पर वरुण गांधी के विवादित बोल

मुलायम को उनके ही बेटे ने पार्टी में किनारे कर दिया

मुलायम सिंह ने साल १९९० में रामभक्तों पर गोलियां चलवा कर पाप किए हैं : पूरनपुर में बोले वरुण गांधी

(संपूर्ण समाचार सेवा) पीलीभीत,

बीजेपी सांसद और पीलीभीत से प्रत्याशी वरुण गांधी ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हुए एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामभक्तों पर गोली चलवाने का पाप करने वाले मुलायम को उनके ही बेटे ने पार्टी में किनारे कर दिया। वरुण ने पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में रविवार को चुनावी सभा में कहा कि एसपी संस्थापक मुलायम ने साल १९९० में रामभक्तों पर गोलियां चलवा कर पाप किए हैं। उनके जीवन के अंत में क्या हुआ उनके अपने बेटे अखिलेश यादव ने धक्का मार कर सड़क पर निकाल दिया। उन्होंने कहा, इस बार लोग कह रहे हैं कि बीएसपी-एसपी एक हो गए हैं। मैं बता दूं, आप सबको कि ये लोग ऊपर से तो एक हो गए हैं लेकिन नीचे से अभी भी एक नहीं हुए हैं। नीचे सब एक-दूसरे से नाराज हैं और अगर ये एक हो भी गए हैं तो ये कौन से खेत की मूली है। इसके अलावा उन्होंने अपने भाषण की शुरूआत में कहा, आप सब ने पिछले बार मुझे तीन लाख वोटों से जिताया था। इस बार और अधिक मतों से विजयी बनाएं। वरुण गांधी ने भरी सभा में मायावती पर टिकट बेच कर राजनीति करने का आरोप लगाया। वरुण गांधी ने कहा, मायावती ने अपने पूरे जीवन में किया ही क्या है उन्होंने तो सिर्फ टिकट ही बेचे हैं। कुछ दिन वरुण की मां और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी सुलतानपुर में रैली के दौरान मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। मेनका इस बार सुलतानपुर से चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामभक्तों पर गोली चलवाने का पाप करने वाले मुलायम को उनके ही बेटे ने पार्टी में किनारे कर दिया। वरुण ने पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र में रविवार को चुनावी सभा में कहा कि एसपी संस्थापक मुलायम ने साल १९९० में रामभक्तों पर गोलियां चलवा कर पाप किए हैं। उनके जीवन के अंत में क्या हुआ उनके अपने बेटे अखिलेश यादव ने धक्का मार कर सड़क पर निकाल दिया। उन्होंने कहा, इस बार लोग कह रहे हैं कि बीएसपी-एसपी एक हो गए हैं। मैं बता दूं, आप सबको कि ये लोग ऊपर से तो एक हो गए हैं लेकिन नीचे से अभी भी एक नहीं हुए हैं।सभा में वरुण गांधी ने मुलायम सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मुलायम सिंह ने रामभक्तों पर गोलियां चलवा कर जो पाप किए हैं, उनकी सजा वह अब भुगत रहे है। उन्होंने कहा, जीवन के अंत में आखिर क्या हुआ उनके बेटे ने ही उन्हें धक्का मारकर रोड पर निकाल दिया। आप लोग ही बताइए कि यह कितने शर्म की बात है। साथ ही उन्होंने कहा, भगवान की लाठी में दम तो होता ही है। अगर आप ने पाप किए है, तो एक न एक दिन ये सब वापस आपके सामने आएंगे।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH